नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 015
दि. 15.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पीएम मोदी 15-20 मई 2026 तक यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर, यात्रा का मुख्य फोकस ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर

(जीएनएस)।

नई दिल्ली , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-20 मई 2026 तक यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रहेंगे. इस यात्रा का मुख्य फोकस ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर है. ईरान युद्ध के मद्देनजर ऊर्जा सप्लाई में रुकावट की वजह से पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-20 मई 2026 तक पांच देशों के दौरे पर जा रहे हैं जिसकी शुरूआत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा से हो रही है. पीएम मोदी यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान से मुलाकात करेंगे. ईरान जंग के बीच जहां दुनिया तेल-गैस की किल्लत से जूझ रही है, माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा पर प्रमुखता से बात करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं.

यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में UAE ने तेल उत्पादक देशों के समूह OPEC+ ढांचे से बाहर निकलने का फैसला किया है. ऐसे में दोनों देशों के लिए प्रत्यक्ष द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी और भी अहम हो गई है, खासकर लंबे समय के लिए एनर्जी सप्लाई और उसके भंडारण में सहयोग के क्षेत्र में.

भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें खास तौर पर ऊर्जा सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श शामिल होगा.

मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष भारत-UAE कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे. यह साझेदारी मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित है. बयान में कहा गया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगी.

भारत और UAE ने पिछले कुछ सालों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ाया है. इसमें कच्चे तेल की आपूर्ति व्यवस्था, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में निवेश और पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर के डाउनस्ट्रीम सेक्टर में सहयोग शामिल है.

वअए फिलहाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और पिछले 25 सालों में भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में सातवें स्थान पर है.

इस यात्रा के दौरान वअए में रहने वाले 45 लाख से अधिक भारतीय समुदाय के कल्याण पर भी खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदाय सबसे बड़े विदेशी समुदायों में से एक माना जाता है.

यूएई के अलावा और किन देशों के दौरे पर जा रहे हैं पीएम

पीएम मोदी के पांच देशों के दौरे का मुख्य फोकस ऊर्जा सहयोग है जिसमें वो नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी बात होगी. प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में शामिल पांच देश हैं- यूएई और यूरोप के चार देश नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली. यूरोपीय देशों के दौरे का मकसद ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बात करना और भारत-यूरोपीय संघ के रिश्तों को मजबूती देना है.

रूस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की

रूसी संघ के विदेश मंत्री, महामहिम श्री सर्गेई लावरोव ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री लावरोव ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दिसंबर 2025 में हुई दोनों नेताओं की बैठक के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। विदेश मंत्री लावरोव और प्रधानमंत्री ने यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया की स्थिति सहित, पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ने के सर्वोत्तम मार्ग के रूप में संवाद और कूटनीति के पक्ष में भारत के सततरुख को दोहराया।

प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री लावरोव से राष्ट्रपति पुतिन को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करने का अनुरोध किया।

पीएम मोदी ने की काफिले में कटौती तो उद्धव गुट ने कहा, 'आप ऐसा मत करिए क्योंकि...'

देश के लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील के बाद अपने काफिले में कटौती की. बुधवार को पीएम मोदी के काफिले में दो गाड़ियां ही दिखीं. जबकि पहले 12-13 गाड़ियां हुआ करती थीं. पीएम मोदी के काफिले में कटौती पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी. 'आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है' शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, "हम प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि आप सुरक्षा में कटौती मत कीजिए. आप देश के प्रधानमंत्री हैं केवल बीजेपी के नहीं हैं. आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. दो गाड़ी में आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी. एसपीजी की गाइडलाइन है, ब्लू बुक का एक नियम है."

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात के सासन गिर में 'लायन' स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज गुजरात के सासन गिर में 'लायन' स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) शिखर सम्मेलन 2026 से पहले आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वर्चुअल माध्यम से की। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में गुजरात के वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया, वन राज्य मंत्री श्री प्रवीण माली तथा आईबीसीए, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

अपने संबोधन में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 'वसुधैव कुटुंबकम' की दूरदृष्टि के लिए धन्यवाद दिया, जिसके कारण आईबीसीए की स्थापना हुई और यह शेरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। उन्होंने शेरों के संरक्षण के प्रति बढ़ती वैश्विक जागरूकता का श्रेय इसी दूरदृष्टि को दिया।

श्री पटेल ने एशियाई शेर के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शेर इस क्षेत्र की लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिसने गिर में एशियाई शेरों की बढ़ती आबादी में योगदान दिया है। श्री पटेल ने कहा कि गिर इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस तरह पारिस्थितिक दृष्टिकोण अपनाकर आर्थिक विकास और वन्यजीव संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न वन्यजीव संरक्षण पहलों के तहत उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी, जिनमें एशियाई शेरों के प्राकृतिक विस्तार के लिए एक नए स्थल के रूप में बर्दा वन्यजीव अभयारण्य का विकास शामिल है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 1 व 2 जून, 2026 को नई दिल्ली में प्रथम आईबीसीए शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। इस दौरान तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 'शेरों को बचाओ, मानवता को बचाओ, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाओ' के नारे के साथ आयोजित इस शिखर सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 95 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, नीति निमार्ता, वैज्ञानिक, संरक्षण कार्यकर्ता, बहुपक्षीय एजेंसियां, वित्तीय संस्थान, सहयोगी संगठन और 400 प्रतिनिधि एक साथ जुटेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आईबीसीए एक वैश्विक गठबंधन है जो सात प्रतिष्ठित बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए समर्पित है, और इसके लिए वह सहयोगात्मक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई और मजबूत वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग का उपयोग करता है।

केंद्रीय मंत्री ने सासन गिर को भारत की समृद्ध जैव विविधता, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि गिर का शेर न केवल गुजरात की पहचान है, बल्कि पूरे देश के गौरव, साहस और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक भी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एशियाई शेरों की जनसंख्या का आकलन करने की पहल, जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव केंद्र की स्थापना और बर्दा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के प्राकृतिक विस्तार के स्थल के रूप में विकसित करने जैसे विभिन्न कदम मिशन मोड में आगे बढ़ाए जा रहे हैं।

श्री यादव ने कहा कि 'लायन' स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम ने शेरों की वैश्विक संरक्षण स्थिति और प्रजाति संरक्षण की दिशा में भारत की पहलों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सफल शेर संरक्षण मॉडल को प्रदर्शित करना, शेरों के निवास स्थान वाले देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, पयार्वास संबंधी दबाव, जलवायु परिवर्तन और मानव-वन्यजीव अंतसंबंध जैसी उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना, ज्ञान का आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है।

श्री यादव ने शेरों को विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और विशालकाय बिल्ली प्रजातियों में से एक बताते हुए कहा कि शेर शीर्ष शिकारी होते हैं जो शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करके, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखकर और जैव विविधता तथा अंतर-प्रजाति संबंधों को आकार देकर एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात कर राज्यों के सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। सीएम योगी, सीएम मोहन यादव और सीएम विष्णु साय ने अमित शाह से की मुलाकात

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात की।

गृह मंत्री से मिले सीएम योगी

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठकों के दौरान सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक पोस्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की।

योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर एक अलग पोस्ट में कहा कि आज मैंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। गृह मंत्रालय ने एक पोस्ट में कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

छत्तीसगढ़ के सीएम ने गृह मंत्री शाह से की मुलाकात

गृह मंत्री के कार्यालय ने एक अन्य पोस्ट में बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गृहमंत्री शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान, सीएम विष्णु साय ने शाह को बस्तर में बदलती स्थिति और चल रही विकास पहलों के बारे में जानकारी दी।

पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश

पीएम मोदी की ओर से की गई ईंधन बचाने की अपील का पश्चिम बंगाल सरकार पर भी असर दिख रहा है, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है, ठीक उसी तरह बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और मंत्री ईंधन को लेकर इसी तरह के उपाय अपनाएंगे. क्या बोले शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के पहले दिन बुधवार (13 मई) को शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के विधायक के तौर पर शपथ ली. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में जो-जो कदम उठाए वे देशहित में उठाए और जनता के हित में उठाए हैं.

रणनीतिक स्वायत्तता और भविष्य के लिए तैयार सैन्य बल के निर्माण हेतु आत्मनिर्भरता एवं संयुक्तता अनिवार्य : रक्षा मंत्री

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु आत्मनिर्भरता एवं संयुक्तता को अनिवार्य बताया है। उन्होंने कहा, ह्लकिसी राष्ट्र की शक्ति तेजी से इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी सेनाएं, प्रयोगशालाएं और रक्षा उद्योग कितनी तत्परता से एकजुट होकर सोचते व कार्य करते हैं।ह्व श्री राजनाथ सिंह 14 मई, 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित कलम एंड कवच 3.0 रक्षा रणनीतिक संवाद के दौरान नीति-निमार्ताओं, सैन्य नेतृत्व, रक्षा उद्योग के हितधारकों, राजनयिकों, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और रणनीतिक विशेषज्ञों को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि भविष्य के युद्धक्षेत्र में सफलता उन्हीं के हाथ लगेगी, जो किसी विचार, प्रोटोटाइप और उसके क्रियान्वयन के बीच के समयांतराल को न्यूनतम कर सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव, जारी संघर्षों, साइबर खतरों, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और हाइब्रिड युद्ध के उभरते स्वरूपों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अब पुराने अनुमानों पर आधारित नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा, ह्लराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारी तैयारी, लचीलापन, नवाचार और रणनीतिक आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक हैं।ह्व

श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता को केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं के लिए अत्यधिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, वह संकट के समय असुरक्षित हो जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा, ह्लहमें अपने राष्ट्रीय तंत्र के भीतर ही प्रमुख रक्षा प्रणालियों का डिजाइन, विकास, उत्पादन, रखरखाव और उन्नयन करना होगा।

पीएम मोदी के यूएई दौरे से पहले हो गया 'शुभ शगुन', रिकॉर्ड तोड़ ट्रेड ने चौंकाया, 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी दौरे से पहले भारत और यूएई की दोस्ती ने इतिहास रच दिया है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जिसे 2022 के 'सेपा' (CEPA) समझौते के तहत तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है. यूएई अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है और दोनों देशों ने अब 2032 के लिए नया टारगेट सेट किया है. अबू धाबीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी की जमीन पर कदम रखने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही भारत और UAE के रिश्तों से एक ऐसी 'गुड न्यूज' आई।

अपर्णा यादव के घर पहुंचकर सीएम योगी ने प्रतीक यादव को दी श्रद्धांजलि, परिवार को बंधाया ढांढस

सीएम योगी ने अपर्णा यादव, उनके बच्चों को ढांढस भी बंधाया. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन पर शोक प्रकट करते हुए पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि दी.

पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया था. सीएम योगी ने अपर्णा यादव, उनके बच्चों व अन्य परिजनों को ढांढस भी बंधाया. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी जताईं.

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

हरियाणा की जनता ने विकास को दी प्राथमिकता

आने वाले समय में यह विश्वास सरकार के लिए प्रेरणा का रत्रोत बनेगा और प्रदेश को और अधिक सशत्त, समृद्ध और प्रगतिशील बनाने में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। हरियाणा में सम्पन्न हुए नगर निकाय चुनावों के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता ने विकास, पारर्दशिता और जनसेवा की नीति पर एक बार फिर अपना अटूट विश्वास जताया है। यह जनादेश केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि जनता के भरोसे, संतोष और अपेक्षाओं का सशत्त प्रतिबिब है। इस व्यापक जनसमर्थन के लिए प्रदेश की जागरूक और सजग जनता का हृदय से आभार व्यत्त किया जाता है, जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रव्रिया में साियि भागीदारी निभाते हुए विकास की दिशा को समर्थन दिया। 10 मई को हुए मतदान के बाद 13 मई की सुबह से शुरू हुई मतगणना में जैसे-जैसे परिणाम सामने आए, यह स्पष्ट होता गया कि प्रदेश की जनता ने स्थिरता, सुशासन और विकास की निरंतरता को प्राथमिकता दी है। सोनीपत, अंबाला और पंचवूला में उल्लेखनीय सफलता तथा अन्य नगर निकायों में व्यापक समर्थन इस बात का संकेत है कि जनता ने सकारात्मक और सरकार की परिणाम आधारित कार्यर्शैली को स्वीकार किया है। यह परिणाम केवल आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि उस विश्वास की अभिव्यत्ति है जो जनता ने वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति व्यत्त किया है। विशेष रूप से रोहतक जिले के सांपला क्षेत्र में प्राप्त सफलता ने प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। लंबे समय से एक विशेष राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में इस प्रकार का जनादेश यह दशार्ता है कि मतदाता अब परंपरागत सीमाओं से आगे बढ़ चुके हैं और वे विकास, पारर्दशिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रहे हैं। सांपला नगरपालिका अध्यक्ष पद पर प्रवीण कोच की जीत और वार्ड स्तर पर विविध परिणाम इस बात का संकेत हैं कि लोकतंत्र में जनता की भूमिका निर्णायक होती है और वही अंततः परिवर्तन की दिशा तय करती है। इसी के साथ ही पंचवूला में श्यामलाल बंसल की जीत भी सरकार के प्रति जनता का विश्वास प्रर्दशित करती है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन ने विकास की इस यात्रा को नई दिशा और गति प्रदान की है। उनके नेतृत्व में देश जिस प्रकार सुशासन, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है, उसी से प्रेरणा लेकर हरियाणा भी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। नीतियों के प्रभावी ियान्वयन और जनकल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में उनकी सोच और दृष्टि का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही यह अभूतपूर्व सफलता हरियाणा सरकार के वुशल, दूरदशा और जन-वेंद्रित नेतृत्व का परिणाम है। हमारी सरकार में प्रशासन को अधिक पारदशा, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए गए हैं। यहां शासन को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि योजनाओं के प्रभावी व्रियान्वयन पर विशेष बल दिया है। हमारी कार्यर्शैली का वेंद्र बिदु यह रहा है कि सरकार का लाभ अंतिम व्यत्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र नागरिक योजनाओं से वंचित न रहे। यह जनादेश केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का संदेश भी है। यह संकेत देता है कि जनता विकास, पारर्दशिता और जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसी दिशा में निरंतर प्रगति देखना चाहती है। आने वाले समय में यह विश्वास सरकार के लिए प्रेरणा का रत्रोत बनेगा और प्रदेश को और अधिक सशत्त, समृद्ध और प्रगतिशील बनाने में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

अग्नि-6 या एमआईआरवी? भारत के सीक्रेट से दुनिया में खलबली, धुएं की लकीर पकड़ने में उलझे चीन-पाक

(जीएनएस)।

भारत ने ओडिशा से मिशन दिव्यास्त्र के तहत टक्क्र तकनीक वाली एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का सफल टेस्ट किया है. इसके साथ ही भारत अब टक्क्र क्षमता वाला छठा देश बन गया है. लेकिन, भारत ने इसके बारे में कुछ भी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है. ऐसे में इस टेस्ट से पैदा हुए धुएं की लकीर खोजने में दुनिया के एक्सपर्ट जुटे हुए हैं. जानकार बता रहे हैं कि भारत ने इस टेस्ट के जरिए कुछ बेहद सीक्रेट हथियार का परीक्षण किया है, जिससे सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान चिंतित हो सकते हैं.

भारत ने बीते 8 मई को इस सीक्रेट हथियार का परीक्षण किया था.

ॲल्व्र 5/ॲल्व्र 6 ङ्ग१ टक्क्र रं४ इं३ ङ ए' इं३: सौ बात की एक बात ये कि आम पब्लिक का तो ज्यादा ध्यान एक खबर पर नहीं गया लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भारत से आई एक खबर से चौंक गए हैं. जी, भारत से आई खबर से. कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं. अनुमान इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा है. तो ऐसा क्या सीक्रेट ऑपरेशन हो गया भारत में? 8 मई की शाम को अंधेरा होते ही ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर सब शांत था. अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई. और आसमान में आग की लपटें देखी गईं. एक विशालकाय मिसाइल आसमान को चीरती हुई ऊपर चढ़ने लगी. उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल के लोग तो क्या, बांग्लादेश तक में लोगों ने आसमान में रोशनी देखी. लोगों ने धुएं की लकीरों का विडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए. रक्षा विशेषज्ञों में चर्चा शुरू हो गई कि ये क्या था? क्या भारत ने कोई नया हथियार टेस्ट किया? क्या भारत ने अग्नि-6 मिसाइल बना ली है? क्या से भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल थी?

दुनिया की निगाहें टिक गईं. लेकिन भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा. एक भी डिटेल नहीं दी. रहस्य और गहरा हो गया. लोग अटकलें लगाने लगे. क्या ये कोई सामान्य टेस्ट था? या कुछ बहुत बड़ा था? और इन सब अटकलों का एक और बड़ा कारण था. और वो था ठडळअट, यानी 'नोटिस यू ऐयरमेन', ये ठडळअट वो होता है जो आसमान के एक इलाके के लिए जारी किया जाता है हवाई जहाजों के लिए. कि इधर मत आना. आपको याद होगा अभी पिछले साल ही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ठडळअट जारी किये जा रहे थे उत्तर भारत के आसमान के लिए. भारत में भी और पाकिस्तान में भी. कि इधर मत आना यहां लड़ाई चल रही है, फाइटर प्लेन आएंगे, मिसाइलें दागी जाएंगी, ड्रोन उड़ाए जाएंगे, तो ये इलाका छोड़ दो. ठडळअट जारी किये गए थे.

कब जारी किया जाता है ठडळअट

ऐसे ही जब कोई मिसाइल टेस्ट होने वाला होता है तो ठडळअट जारी किया जाता है. पहले भी जब-जब ओडिशा में भारत अपनी मिसाइलें टेस्ट करता रहा है तो ठडळअट जारी करता रहा है. लेकिन पहले ये ठडळअट होते थे 1500-2000 किलोमीटर के आसमान के इलाके के लिए. लेकिन इस बार ठडळअट जारी किया गया 3500 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके के लिए. ये बहुत ही लंबा कॉरिडोर था. ठडळअट ने बंगाल की खाड़ी में 3,560 ' लंबा खतरे का क्षेत्र घोषित किया इस बार. ये ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से शुरू होकर दक्षिण में हिंद महासागर के बहुत गहरे इलाके तक जा रहा था.

तो ये अटकलें जोर पकड़ने लगीं कि कहीं भारत अग्नि-6 तो टेस्ट नहीं कर रहा. अग्नि-6 जो भारत बनाने वाला है उसकी रेंज 8000-10000 किलोमीटर होने वाली है. या फिर भारत कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तो टेस्ट करने नहीं जा रहा? कुछ कहने लग गए कि ये भारत की कोई हाइपरसॉनिक मिसाइल हो सकती है या कोई नया सीक्रेट हथियार हो सकता है. और अजीब ये भी था कि इस बार ठडळअट कई दिनों के लिए जारी किया गया था. इसलिए कई तरह की अटकलें लगनीं शुरू हो गईं थी. फिर अगले दिन, यानी 9 मई को रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार ऐलान किया कि 'मिशन दिव्यास्त्र' सफल रहा.

क्या था मिशन दिव्यास्त्र?

तो क्या था मिशन दिव्यास्त्र? ये था ऐडवांस्ड अग्नि मिसाइल का टेस्ट, टक्क्र नाम की खतरनाक तकनीक के साथ. टक्क्र मतलब 'मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री वेहिकल'. यानी एक ही मिसाइल में कई 'वॉरहेड' लगे होते हैं, वैसी मिसाइल. यानी एक मिसाइल आसमान में ऊंची जाती है, फिर कई छोटे-छोटे वॉरहेड अलग होते हैं, अलग-अलग बम एक तरह से, और हर एक अपना अलग टारगेट चुनकर हमला करता है. साथ में 'डिकॉय' यानी नकली बम भी छोड़ देती है. दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए. कौन सा असली है, कौन सा नकली? कौन कहां जा रहा है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता. इस मिसाइल टेस्ट में हिंद महासागर के बड़े इलाके में कई अलग-अलग टारगेट को एक साथ मारा गया.

यानी एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई बेस पर हमला किया जा सकता है. सब एक साथ. और दुनिया इससे क्यों चौंक गई? क्योंकि अब तक सिर्फ 5 देशों के पास ये टक्क्र तकनीक है. अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन. भारत छठा देश बन गया. और अग्नि सीरीज की ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार कर सकती है. यानी चीन के किसी भी कोने तक, पाकिस्तान के किसी भी कोने तक. पूरा एरिया कवर कर सकती है. लेकिन भारत ने कोई डिटेल नहीं बताई. मिसाइल का सटीक रेंज कितनी है, नहीं बताया. कितने वॉरहेड ले जा सकती है, नहीं बताया. कितनी स्पीड है, नहीं बताया. सब सीक्रेट. सिर्फ इतना कहा कि सभी टारगेट सफल रहे, सारा मिशन ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ.

ताकत का अंदाजा लगाती रहे दुनिया

ये सोचा-समझा प्लैन है. कि हमारी ताकत का अंदाजा लगाती रहे दुनिया. और दुनिया अब तक अंदाजा लगा रही है. क्योंकि जो विडियो लोगों ने रिकॉर्ड किए उनमें दिखा कि धुएं और आग से जो लकीर आसमान में बनी वो वैसी नहीं थी जो पहले की अग्नि मिसाइलों में होती थी. ट्रेल बीच में मुड़ गई, टेढ़ी-मेढ़ी हो गई, जिग-जैग करती हुई आगे बढ़ी. जैसे बीच हवा में दिशा बदलकर दुश्मन को चकमा दे रही हो. ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक में ये ट्रेल दिखी आसमान में. और बीच रास्ते में मुड़ने का काम तो हाइपरसॉनिक मिसाइल कर सकती है. इसलिए भारत सरकार के कहने के बाद भी कई रक्षा विशेषज्ञ दुनिया के ये अटकलें लगा रहे हैं धुएं की ट्रेल से कि ये अग्नि-6 का कोई पहला चरण भी हो सकता है. क्योंकि वो हवा में रास्ता बदलने वाली मिसाइल बनाने वाला है भारत. लेकिन एक आकलन ये भी है कि ये टक्क्र का जादू हो सकता है. फायर होने के बाद हो सकता है कि मिसाइल का ढइश यानी पोस्ट-बूस्ट वेहिकल ऊपर जाकर मुड़-मुड़कर कई वॉरहेड अलग-अलग दिशाओं में छोड़ता हो इसलिए ये धुएं की टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें दिखी हों आसमान में. या फिर हर वॉरहेड खुद मुड़कर दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कनफ्यूज करने वाला हो इस मिसाइल में.

अऊश्एफ्ळक्रएटएठळ

भारत के पास ये कौन सी तकनीक

कौन सी तकनीक है ये भारत के पास इसकी चर्चा हर मिलिटरी एक्सपर्ट कर रहा है. कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये हाई ऑल्टीट्यूड विंड शियर का असर हो सकता है. यानी सिंपल भाषा में ये कि हवा के जोर ने धुएं की लकीर को टेढ़ा कर दिया हो. लेकिन ज्यादातर ऐनलिस्ट ये मान रहे हैं कि ये मिसाइल ऐसी थी जिससे जो अलग-अलग दिशा में वॉरहेड आसमान में निकले, बम जो अलग-अलग गये उन सब में अलग-अलग टार्गेट फीड थे और वो अपना अलग रास्ता बना कर गए इसलिए धुएं की लकीर ऐसी छोड़ते हुए गए कि आसमान में जिग-जैग पैटर्न बन गया. यानी एक मिसाइल ऊपर गई और उससे फिर कई अलग-अलग मिसाइलें या बम निकल कर अपने अपने रास्ते चल दिए अपने-अपने टारगेट की तरफ. लेकिन ऊफ्ळ्ढ ने एक शब्द नहीं कहा. बस इतना कि सभी टारगेट हिट हुए, मिशन पूरा हुआ. मिशन दिव्यास्त्र. सौ बात की एक बात.

ट्रंप ने तोड़ी 45 साल पुरानी कसम, जिनपिंग के साथ शराब पीते वीडियो वायरल, दुनिया दंग!

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सख्त जीवनशैली और शराब से कोसों दूर रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चीन से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसमें ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक राजकीय भोज के दौरान जाम टकराते और उसका घूंट लेते नजर आ रहे हैं।

1981 में एक पारिवारिक त्रासदी के बाद उन्होंने जिस चीज को कभी हाथ न लगाने की कसम खाई थी, क्या बीजिंग की इस शाम उन्होंने वो नियम बदल दिया? आइए जानते हैं इस दुर्लभ पल के पीछे की पूरी कहानी।

बीजिंग के 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के सम्मान में एक शानदार दावत दी। इस दौरान डिप्लोमैटिक टोस्ट (ऊ्र'ङ्ग३ ळङ्ग२३) यानी सम्मान में जाम टकराने की रस्म हुई। वायरल वीडियो में ट्रंप शैंपेन का गिलास हाथ में लिए और उसका एक प्रतीकात्मक घूंट लेते नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह शायद पहली बार है जब ट्रंप को सार्वजनिक रूप से शराब पीते देखा गया है, क्योंकि वे हमेशा इससे बचते रहे हैं।

क्यों छोड़ दी थी शराब?

डोनाल्ड ट्रंप के शराब न पीने के पीछे एक भावुक वजह रही है। 1981 में उनके बड़े भाई फ्रेड ट्रंप की मौत शराब की लत के कारण हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वे कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। पिछले 45 सालों में उन्हें कभी किसी पार्टी या समारोह में शराब पीते नहीं देखा गया। यहाँ तक कि 2017 की चीन यात्रा पर भी उन्होंने शराब से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग था।

चीन की परंपरा और दोस्ती का जाम

चीन में राजकीय भोज के दौरान शराब परोसना केवल भोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्राचीन परंपरा है। झौ और तांग जैसे महान राजवंशों के समय से ही इसे मित्रता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। शी जिनपिंग के हर बड़े आयोजन में 'माओताई' जैसी पारंपरिक चीनी शराब परोसी जाती है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने इस बार मेजबान देश की संस्कृति और राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को किनारे रखकर जाम का एक घूंट लिया।

शाही मेन्यू: क्या-क्या था खास?

इस राजकीय भोज का खाना बेहद शाही और पारंपरिक चीनी स्वाद से भरपूर था। मेन्यू में स्टार्टर के साथ टमाटर के सूप में लॉबस्टर, मशहूर बीजिंग रोस्ट डक और क्रिस्पी बीफ रिब्स जैसे पकवान शामिल थे। इसके अलावा सरसों की चटनी में तैयार सैल्मन मछली और मीठे में तिरामिसू व आइसक्रीम का भी इंतजाम था। इस खास दावत के दौरान ट्रंप और जिनपिंग एक ही टेबल पर बैठे थे, जहाँ दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच आपसी रिश्तों पर चर्चा हुई।

लब्बैक या रसूल अल्लाह की पोस्ट और बेटा जेल में... लखनऊ की गोसाईगंज जेल पहुंचे पिता ने रो-रोकर सुनाई आपबीती

एटीएस द्वारा देश विरोधी गतिविधि के आरोप में गिरफ्तार गयास के पिता तौफीक ने लखनऊ की गोसाईगंज जेल में बेटे से मुलाकात की। उन्होंने बेटे को बेगुनाह बताते ..

लखनऊ की गोसाईगंज जेल में गयास से मिलकर आए पिता तौफीक ने की निष्पक्ष जांच की मांग

(जीएनएस)।

रामपुर। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए गयास ने इंटरनेट मीडिया पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की पोस्ट की थी, जिसके बाद आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने उसे गिरफ्तार कर लिया और लखनऊ ले गई। उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। वह लखनऊ की गोसाईगंज जेल में निरुद्ध है।

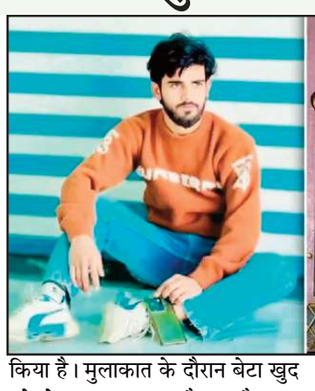

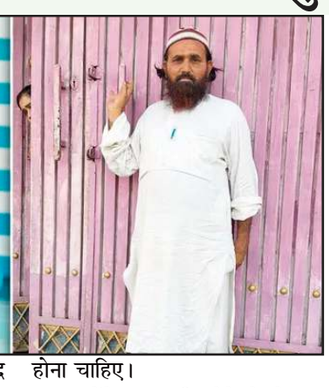

बुधवार को गयास से उसके पिता तौफीक ने जेल में मुलाकात की। बेटे से मिलकर लौटे पिता ने बताया कि बेटे ने देश विरोधी कोई काम नहीं किया है। मुलाकात के दौरान बेटा खुद को बेगुनाह बता रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह की पोस्ट करने पर उसे गिरफ्तार किया गया। इसका अर्थ है कि हम हाजिर हैं।

उन्होंने बताया कि जेल में मुलाकात के दौरान बेटे ने जानकारी दी कि एक बार एटीएस की टीम उसे घर छोड़ने के लिए जा रही थी। कुछ देर बाद एक फोन आने पर दोबारा वापस ले गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बेटे के साथ इंसाफ होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि बेटे से दो बार मुलाकात हुई। 12 मई को एटीएस ने उसे न्यायालय में पेश किया था। तब बेटे से मिले थे। इसके बाद उसे जेल भेज दिया। दूसरी बार जेल में जाकर मिलकर आए हैं। अब चार जून को न्यायालय में तारीख है। बेटे की पेशी कराई जाएगी। तब फिर जाकर मिलेंगे और उसके मुकदमे की पैरवी करेंगे।

सिविल लाइंस क्षेत्र के ताश का मझरा निवासी तौफीक मंडी समिति में आढ़त का काम करते हैं। वह मूल रूप से थाना शहजादनगर के चमरौआ गांव के रहने वाले हैं। चार साल पहले ताश का मझरा में घर बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं। उनके सात बच्चे हैं।

इनमें 22 साल का गयास पाशा तीसरे नंबर का है। वह आठवीं पास है और एसी मैकेनिक है। छह माह पहले सऊदी अरब काम करने गया था। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात होने पर वापस आ गया था। यहां आने के बाद वह दिल्ली काम करने चला गया था। छह मई को एटीएस की टीम उसके घर ताश का मझरा पहुंची थी।

टीम ने स्वजन से गयास के बारे में जानकारी की। कुछ और जानकारी के लिए उसे दिल्ली से बुलवा लिया। सात मई को गयास जैसे ही मुरादाबाद तक पहुंचा तो टीम ने मुरादाबाद स्टेशन से उसे हिरासत में ले लिया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर 12 मई को लखनऊ न्यायालय में पेश किया और वहां से जेल भेज दिया था।

'ग्लोबल साउथ की ताकत बनेगा यह संगठन', पहले दिन की बैठक के बाद बोले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर

(जीएनएस)।

भारत में ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक का आगाज हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बदलती वैश्विक स्थितियों के बीच हो रही यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। जयशंकर ने पहले दिन की बैठक के बाद सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा कि ब्रिक्स आज दुनिया में सुधार और बदलाव का सबसे बड़ा मंच बन चुका है।

भारत की अध्यक्षता में इस बार का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स को और अधिक लचीला, आधुनिक और 'ग्लोबल साउथ' की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाना है, ताकि यह आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके।

दुनिया के लिए एक मजबूत विकल्प

एस. जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स की असली ताकत इसकी स्वतंत्रता और विविधता है। आज दुनिया इस संगठन को बहु-ध्रुवीयता (ट४'३-स्रङ्ग'१३८) के प्रतीक के रूप में देख रही है। यह न केवल देशों को जोखिम कम करने के विकल्प देता है, बल्कि संप्रभु समानता और आपसी सम्मान की कद्र भी करता है। जयशंकर के मुताबिक, न्यू डेवलपमेंट बैंक (ठउइ) जैसे संस्थानों ने यह साबित कर दिया है कि ब्रिक्स अब वैश्विक संस्थाओं का एक भरोसेमंद और ठोस विकल्प बन चुका है।

ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा भारत

भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का पूरा ध्यान विकासशील देशों यानी 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं पर है। जयशंकर ने बताया कि हम सप्लाई चेन को मजबूत करने और बाजारों में विविधता लाने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, आपदाओं से पहले चेतावनी देने वाले सिस्टम और जलवायु परिवर्तनों को झेल सकने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल एकीकरण के जरिए सामाजिक कल्याण को हर व्यक्ति तक पहुंचाना भारत का मुख्य लक्ष्य है।

नवाचार और युवाओं के लिए नए अवसर

ब्रिक्स देशों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। जयशंकर ने 'ब्रिक्स इनक्यूबेटर नेटवर्क' और 'यूथ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म' का जिक्र किया, जो सदस्य देशों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे। इसके साथ ही, विज्ञान और अनुसंधान के लिए एक साझा रिपोजिटरी तैयार की जा रही है, ताकि शोध और नई तकनीकों का लाभ सभी सदस्य देशों को समान रूप से मिल सके।

व्यापार और स्वास्थ्य में गहरा सहयोग

व्यापार को आसान बनाने के लिए 'इफ्क्रउर टरटए कनेक्ट पोर्टल' और व्यापारिक लेन-देन के लिए नई प्रणालियों पर चर्चा की गई। जयशंकर ने कहा कि हमारा मकसद छोटे और मध्यम उद्योगों को एक-दूसरे से जोड़ना है।

इसके साथ ही खेती और स्वास्थ्य के क्षेत्र में साझेदारी को और गहरा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि ये साझा प्रयास ब्रिक्स को और भी फुतीर्ला और आधुनिक बनाएंगे, जिससे आपसी सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा

विदेश मंत्री ने 'सस्टेनेबिलिटी' यानी टिकाऊ विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्तों पर ध्यान देना जरूरी है।

18-19 मई को लखनऊ में सजेगा दिग्गजों का महाकुंभ; 'विचार, प्रभाव व पहचान' इसलिए खास हैं वक्ता

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ आगामी 18 और 19 मई को देश के चर्चित चेहरों, विचारों और विमर्श का केंद्र बनने जा रही है। 78 वर्षों का गौरवशाली इतिहास समेटे और स्वर्णिम शताब्दी की ओर तेजी से बढ़ रहे अमर उजाला समूह का महाआयोजन 'अमर उजाला संवाद उत्तर प्रदेश 2026' राजधानी में सजने जा रहा है। राजधानी के होटल द सेंट्रम में आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राजनीति, अध्यात्म, उद्योग, सिनेमा, खेल और समाज के बड़े चेहरे जनता से सीधे संवाद करेंगे।

कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे वक्ता केवल अपने क्षेत्र के चर्चित नाम नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों, कार्यों और हालिया गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बहस और चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर फिल्म कलाकार, उद्योगपति से लेकर आध्यात्मिक गुरु तक हर वक्ता अपने साथ अनुभव,संघर्ष और बदलते भारत की कहानी लेकर आ रहा है।

ये वक्ता करेंगे शिरकत

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। आध्यात्मिक जगत से गौर गोपाल दास और स्वामी चिदानंद सरस्वती शामिल होंगे। वहीं राजनीति के मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शिरकत करेंगे। सिनेमा जगत से जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा, वरुण धवन, रिचा चड्ढा, मृणाल ठाकुर और श्वेता त्रिपाठी संवाद का हिस्सा बनेंगे। खेल जगत से पूर्व क्रिकेटर एवं राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू और पहलवान संग्राम सिंह भी शामिल होंगे। प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी भारतीय खानपान और फूड कल्चर पर विशेष सत्र में अपने विचार साझा करेंगे। दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 16 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें धर्म, राजनीति, अध्यात्म, खेल, एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, शिक्षा, रक्षा और आर्थिक विकास जैसे समकालीन विषयों पर चर्चा होगी। अगर आप भी इस संवाद का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अमर उजाला ऐप डाउनलोड कर अभी रजिस्ट्रेशन करें।

लखनऊ में हाई सिक्योरिटी जोन में कार सवार का दुस्साहस, स्कूटी सवार को कुचलने का प्रयास

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के ऐसे क्षेत्र में एक कार सवार ने दुस्साहस का प्रयास किया, जहां सड़क के दोनों तरफ हाई सिक्योरिटी का जोन है। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों वाले लोक भवन और विधान भवन के सामने हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र में विधान भवन गेट नंबर-8 के पास एक रईसजादे ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया।

यहां पर एक विचित्र ने मामला सामने आया है। कार सवार युवक ने स्कूटी सवार को डराने-धमकाने के साथ उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हालांकि देर शाम तक पीड़ित की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई थी।

ताजमहल में शाही मस्जिद में लौटेगी रंगत, अरकने संवारने का ए

वायरल वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। वीडियो में होंडा सिटी कार संख्या यूपी 32 एफजे 9191 स्कूटी सवार युवक का पीछा करती दिखाई दे रही है। आरोप है कि कार चालक लगातार तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मारने का प्रयास कर रहा था। साथ ही बार-बार हॉर्न बजाकर युवक को डराने की कोशिश भी की गई।

इसी दौरान स्कूटी सवार युवक गुस्से में वाहन रोककर कार के पास पहुंचा और शीशे पर हाथ मारते हुए चालक से विरोध जताया। युवक ने कार चालक से कहा कि अगर हिम्मत है तो गाड़ी चढ़ाकर दिखाए। इसके बाद कार चालक ने पहले वाहन पीछे किया और फिर तेजी से युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक किसी तरह बच गया, लेकिन स्कूटी कार की चपेट में आ गई।

घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। हजरतगंज पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

'उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश बना दिया था', सीएम योगी ने बताया- कैसे लिखी गई यूपी के विकास की पहली इबारत

लखनऊ के होटल ताज में टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से '09 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी' कॉन्क्लेव आयोजित की गई। इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार की विकास की नीति और दिशा क्या है।

(जीएनएस)।

लखनऊः टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से लखनऊ के होटल ताज में आयोजित '9 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी' कॉन्क्लेव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 2017 में जब राज्य में उनकी पहली सरकार आई थी तो कैसे उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारकर देश का ग्रोथ एंजिन बनाने की तैयारी की गई थी।

उत्तर प्रदेश 'प्रश्न प्रदेश' बना दिया गया था

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, आज से 9, 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को लोगों ने 'प्रश्न प्रदेश' बना दिया था। नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, पर्व त्यौहार पर उत्सव नहीं उपद्रव

शुरू हो जाते थे। गुंडागर्दी चरम पर थी, सरकार के समानांतर माफिया, गुंडे सत्ता का संचालन करते थे। नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं थी, भाई-भतीजावाद था। बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थीं। परंपरागत उद्यम दम तोड़ रहे थे, सरकार की न कोई पॉलिसी थी, न नीयत थी, न ही नीति ही थी।

उन्होंने कहा कि, इसका परिणाम क्या होता? उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनना ही था। किसान की लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था। न तकनीक थी न बिजली थी। बीज नहीं था, बाजार नहीं था, किसान के सामने आत्महत्या के सिवाय कुछ बचता ही नहीं था। कोई दूसरा रोजगार नहीं था।

कैसे बदला उत्तर प्रदेश का भविष्य?

मुख्यमंत्री ने कहा कि, अराजकता, निराशा, असुरक्षा भरे उस माहौल में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। सरकार जब बनी तो हमने एक महीने तक एक ही काम किया। मैं मंत्रिमंडल के सहयोगियों को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बिठाता था। केवल दो मुद्दों पर चर्चा करते थे, विभागों के प्रजेंटेशन होते थे, चर्चा होती थी, कार्ययोजना बनती थी। लोगों को यह समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि इस प्रजेंटेशन, कार्ययोजना में छिपा हुआ है नए उत्तर प्रदेश का भविष्य, जो अब बीमारू राज्य से नए भारत के ग्रोथ एंजिन की नई यात्रा को प्रारंभ करने वाला है।

अब विकास कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि, अब विकास केवल लखनऊ,वाराणसी, गोरखपुर तक ही सीमित नहीं है। विकास अब सभी 75 जनपदों में एक साथ चलता है। बिजली केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, बल्कि सभी 75 जनपदों में और सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है, कोई भेदभाव नहीं होता।

अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस

उन्होंने कहा कि, उत्तरप्रदेश के अंदर विकास का पैमाना व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं है, उसका आधार सबका साथ, सबके विकास का है। उसका मंत्र यही है कि हम विकास सबका करेंगे, लेकिन उत्तरप्रदेश को बर्बाद करने वाली तुष्टिकरण की नीति से हम उतनी ही दूरी भी बनाएंगे। अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो हमने पहले दिन अपनाई थी, वह लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आज भी जारी है।

दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी चलेंगी मेट्रो फीडर बसें

दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश में मेट्रो फीडर बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के पीछे मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ाने का मकसद है।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मेट्रो एवं सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो यात्रियों की संख्या बढ़ाने और अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में मेट्रो और सिटी ट्रांसपोर्ट के बीच बेहतर समन्वय, पार्किंग सुविधा विस्तार और फीडर सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विस्तार से चर्चा की गई।

सबसे ज्यादा लखनऊ में चलेंगी बसें

बैठक में जानकारी दी गई कि लखनऊ में लगभग 71, कानपुर में 24 और आगरा में 19 नए पार्किंग स्थलों को अंतिम रूप दिया गया है। नगर निगम द्वारा इनकी निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों तक पहुंच आसान बनाने के लिए फीडर कनेक्टिविटी को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ में 29, कानपुर में 50 और आगरा में 27 नए ऑटो एवं टेम्पो सर्कुलर रूट तय किए गए हैं।

शटल बस सेवाएं शुरू की जाएंगी

इन मार्गों पर नए स्टॉप भी विकसित किए जाएंगे, ताकि यात्रियों को निर्बाध परिवहन सुविधा मिल सके। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी सहमति बनी है, जिसे सोशल मीडिया, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और अन्य माध्यमों से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी आवासीय कॉलोनियों और कार्यालयों को नजदीकी मेट्रो स्टेशनों से जोड़ने के लिए शटल बस सेवाएं चरणबद्ध रूप से शुरू करने की योजना है।

ओला-उबर और रैपिडो के साथ खास प्लान तैयार

अंतिम मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ऐप आधारित सेवाओं जैसे UTU Mobility के साथ-साथ ओला, उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं के समन्वय को भी मजबूत किया जा रहा है। बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने कहा कि मेट्रो सेवाओं को और अधिक आसान एवं जनसुलभ बनाने के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करना बेहद जरूरी है।

सुशील कुमार ने बताया कि विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के आसपास पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है, ताकि यात्रियों को अपने निजी वाहनों की सुरक्षित पार्किंग की सुविधा मिल सके और अधिक से अधिक लोग मेट्रो सेवा का उपयोग करने के लिए प्रेरित हों। वहीं, बैठक के आखिर में मंडलायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस ने बाइक सवार को कुचला, 150 फीट तक घसीटा; हमीरपुर के युवक की दर्दनाक मौत

(जीएनएस)।

फतेहाबाद (आगरा)। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सहित युवक बस के नीचे फंस गया। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने शो मचाकर चालक को बस रोकने का इशारा किया।

बावजूद इसके चालक ने बस को दौड़ते हुए युवक सहित बाइक को 150 फीट तक घसीटा। बाद में चालक और सह चालक बस को छोड़कर फरार हो गए। बस में 80 यात्री सवार थे।

घायल युवक को एसएन मेडिकल कालेज की इमरजेंसी भेजा गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक नोएडा में प्राइवेट नौकरी करता था।

हमीरपुर के गांव रतवा खन्न निवासी 27 वर्षीय सत्यवीर नोएडा में प्राइवेट नौकरी करते थे। गुरुवार सुबह वह घर से बाइक लेकर नोएडा जाने के लिए निकले थे।

थाना बमरौली कटारा क्षेत्र में सुबह 10 बजे लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 4.700 पर बिहार से दिल्ली जा रही आनंद ट्रैवल्स की बस ने ओवरटेक करते समय बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवक बस के नीचे फंस गया।

पास से गुजर रहे कार सवारों ने शोर मचाते हुए चालक को बस रोकने का इशारा किया। चालक ने बस को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए बाइक सहित युवक को 150 फीट तक घसीटा। इसके बाद बस को पीली पट्टी के पास खड़ा कर चालक और सह चालक फरार हो गए।

बाइक में बस की टक्कर लगने से हुए तेज धमाके की आवाज सुनकर बस में सवार यात्रियों में भी चीख पुकार मच गई। बस रुकते ही यात्री भी नीचे उतर आए।

सूचना पर यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी सुधीश कुमार शुक्ला, थाना बमरौली कटारा पुलिस, चौकी प्रभारी नदोता, सेफ्टी एटलस टीम, एसएसडी तथा यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। घायल को एंबुलेंस की मदद से एसएन मेडिकल कालेज की इमरजेंसी भेजा।

यहां डाक्टर ने इलाज के दौरान सत्यवीर को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार के पास से मिले आधारकार्ड से उसकी पहचान हुई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा।

यूपीडा की टीम ने क्रेन की मदद से बस और बाइक को एक्सप्रेसवे से हटवाकर बमरौली कटारा थाने पहुंचाया। थाना प्रभारी बमरौली कटारा दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि युवक के स्वजन को हादसे की सूचना दी गई है। चालक और सह चालक की तलाश की जा रही है।

लखनऊ जंक्शन पर बड़ा हादसाः स्टेशन के एक हिस्से की छत भरभराकर गिरी, बाल-बाल बचे यात्री

(जीएनएस)।

लखनऊ। बिना अनुमति के लखनऊ जंक्शन की बंद पड़ी कैंटीन की दीवार को तोड़ने के दौरान एक पिलर टूट गया। इस कारण लखनऊ जंक्शन के महिला प्रतीक्षालय के हिस्से को लेते हुए छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। छत जिस स्थान पर गिरी, उसके ठीक बगल के वेटिंग रूम में 90, और ऊपर लगभग 110 यात्री बैठे थे।

कार्यस्थल से कुछ देर पहले ही 10 श्रमिक वहां से दूसरी जगह गए थे। इस मामले को लेकर रेलवे लीपापोती करता रहा। वह अपने को बचाने के लिए गेंद रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और आईआरसीटीसी के पाले में डालता रहा। देर शाम तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर ही नहीं पहुंचा।

वहीं, सुरक्षा को देखते हुए तीनों प्रतीक्षालयों से यात्रियों को निकालकर उसे बंद कर दिया गया है। अब यात्रियों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। घटना शाम करीब चार बजे की है। लखनऊ जंक्शन में प्रवेश करते ही बायीं ओर आईआरसीटीसी की रेल आहार कैंटीन चलती थी।

इस कैंटीन को बंद कर दिया गया था। आईआरसीटीसी ने कैंटीन को रेलवे को दो माह पहले ही सिपुर्द कर दिया था। कैंटीन के ठीक बगल में यात्री प्रतीक्षालय है जहां यात्रियों का सामान रखने के लिए एक लाकर रूम भी है। इसी हिस्से को विस्तार देने के लिए बंद पड़ी 40 गुणे 40 फीट की कैंटीन के पिछले हिस्से की दीवार तोड़ने का काम पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने ठेकेदार को दिया था।

ठेकेदार ने 10 श्रमिक को लगाकर दीवार को तोड़ने का काम शुरू किया। बिना सुरक्षा उपाय के दीवार तोड़ते ही एक पिलर टूट गया। पिलर पर ऊपर बने महिला प्रतीक्षालय का भार था। पिलर टूटते ही महिला प्रतीक्षालय के शौचालय वाले हिस्से के साथ करीब 40 गुणे 40 फीट की छत गिर गई।

छत गिरते ही तेज धमक से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। उसका मलबा पूरे परिसर में फैल गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर दी गई। उसके बगल वाले यात्री प्रतीक्षालय और प्रथम तल पर स्थित महिला व पुरुष एसी यात्री प्रतीक्षालय से करीब 200 यात्रियों को हटाया गया। तीनों ही प्रतीक्षालयों को बंद कर दिया गया है।

बिना अनुमति हो रहा था काम

जिस हिस्से की दीवार को तोड़ा गया, उसका काम ठेकेदार ने बिना स्टेशन प्रशासन की अनुमति के ही शुरू किया था। यह काम इंजीनियरिंग और वाणिज्य अनुभाग के बीच बिना अनुमति के हो रहा था। इस कारण ही देर शाम तक उनकी ओर से आरपीएफ में कोई लिखित सूचना तक नहीं दी गई।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने कहा कि काम आईआरसीटीसी करा रहा था। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि दो महीने पहले ही बंद कैंटीन रेलवे को वापस सौंप दी गई थी। उनकी ओर से कोई काम नहीं हो रहा था।

रोडवेज कर्मी 26 मई को लखनऊ में एमडी का करेंगे घेराव, लंबित मांगों पर प्रदर्शन की तैयारी

(जीएनएस)।

कानपुर। विभिन्न लंबित मांगों के संबंध में उप्र रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने 26 को लखनऊ में प्रबंध निदेशक के घेराव करने की घोषणा भी कर दी है।

इससे पहले वह लोग 18 मई को क्षेत्रीय प्रबंधक को मांग पत्र देंगे। पदाधिकारी संगठन सदस्यों को एकजुट करने में बैठकें भी कर रहे हैं। बुधवार को किदवईनगर डिपो पर संगठन नेताओं ने संविदा व नियमित कर्मियों के साथ बैठक कर एमडी के घेराव कार्यक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दी है।

क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेश अग्निहोत्री और संयुक्त प्रांत मंत्री राजेश द्विवेदी ने कर्मियों से कहा कि नेतृत्व संगठन की मांगों पर विचार नहीं कर रहा है। बस अड्डों के आसपास डग्गामार वाहनों के संचालन को रोका नहीं जा रहा है। निगम का लगातार निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

बस अड्डों का पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) माडल और कार्यशालाओं को निजी हाथों में दे दिया जा रहा है। संगठन की मांग है कि संविदा कर्मी नियमित हों या उनका मानदेय न्यूनतम 25,000 रुपये हो। अभी 2.25 रुपये प्रति किमी के हिसाब में उन्हें मानदेय मिल रहा है।

बैठक में एके सिंह, क्षेत्रीय मंत्री अमित तिवारी, किदवईनगर शाखा के अध्यक्ष निखिल त्रिपाठी व मंत्री ब्रजेश पांडेय भी थे।

प्रधान और भाई पर दिनदहाड़े किया हमला, लखनऊ रेफर

(जीएनएस)।

तिलोई। मोहनगंज के शाहमऊ कस्बे में बृहस्पतिवार को दिनदहाड़े ग्राम प्रधान और उनके भाई पर हमला कर दिया गया। एसयूवी से पहुंचे नकाबपोश दबंगों ने दोनों को सरिया, हॉकी और डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

सिंहपुर मजरे ढोढनपुर निवासी ग्राम प्रधान अब्दुल कादिर उर्फ खान ने बताया कि वह अपने भाई साहब के साथ शाहमऊ में इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से एसयूवी सवार छह से अधिक नकाबपोश पहुंचे और हमला बोल दिया। हमलावरों ने दोनों भाइयों को दौड़ाकर पीटा। जान बचाकर भाग रहे भाई को सड़क पर गिराकर घसीटते हुए मारा गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया।

थाना प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ में छिपकर रह रहा 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, परिवार के सदस्य पर की थी कई राउंड फायरिंग

(जीएनएस)।

लखनऊ। चंदौली जिले से 50 हजार रुपये का इनामी और लंबे समय से फरार चल रहे आशुतोष सिंह को एसटीएफ ने गुरुवार को आशियाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित चंदौली के सैयदराजा थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था।

एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित आशुतोष सिंह चंदौली के सैयदराजा के फेसुड़ा गांव का रहने वाला है। उसे गुरुवार को आशियाना स्थित मां गायत्री स्वीट्स एंड नमकीन के पास, नाबार्ड बैंक और पावर हाउस रोड के पास से गिरफ्तार किया है।

बताया कि पिछले कई दिनों से फरार और इनामी अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएं मिल रही थीं। इसी दौरान सूचना मिली कि चंदौली के सैयदराजा थाने में दर्ज मुकदमे का वांछित अभियुक्त लखनऊ में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि जून 2025 में पारिवारिक संपत्ति की पैमाइश के दौरान उसका अपने ही परिवार के शैलेंद्र कुमार सिंह से विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद के दौरान उसने अपने साथी गोलू उर्फ राजीव सिंह के साथ मिलकर शैलेंद्र सिंह को जान से मारने की धमकी दी और कई राउंड हवाई फायरिंग की थी।

घटना के बाद उसके खिलाफ सैयदराजा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था और लखनऊ में छिपकर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपित के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2018 में उसके खिलाफ सैयदराजा थाने में लूट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल अभियुक्त को संबंधित थाने में दाखिल कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

आम लोगों के बीच पल रहा था आतंक! दिल्ली-फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में रडार पर लखनऊ के कई सफेदपोश

(जीएनएस)।

लखनऊ। दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके और फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद शुरू हुई जांच अब आर्थिक नेटवर्क, डिजिटल संपर्कों और संदिग्ध लोगों तक पहुंची है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इसके तार लखनऊ से जुड़ते गए।

फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. शाहीन सईद और उसके भाई डा. परवेज अंसारी को लेकर एटीएस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने राजधानी में तेजी से जांच की। सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद डाक्टर भाई-बहन समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

जांच में लखनऊ का नाम सामने आने पर सभी चकित रह गए। हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर वह कौन आतंकी है, जो आम लोगों के बीच रह रहा है। 12 नवंबर 2025 को एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लखनऊ के खंदारी बाजार और आइआइएम रोड स्थित घरों पर छापा मारा था।

जांच एजेंसियों ने इन स्थानों पर छापेमारी कर मोबाइल फोन, लैपटाप, पेन ड्राइव, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए। एजेंसियों को संदेह है कि इन्हीं उपकरणों के जरिए संपर्क और नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।

जांच में यह भी सामने आया कि डॉ. शाहीन और डा. परवेज लखनऊ में सात से आठ लोगों के लगातार संपर्क में थे। इनमें कुछ लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं।

एटीएस ने उनकी काल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और डिजिटल लेनदेन की जांच शुरू कर दी है। एलआइयू की मदद से इन संदिग्ध संपर्कों की तलाश की जा रही है। कई लोगों के नंबर बंद मिले हैं, जबकि कुछ ने हाल में अपने ठिकाने बदल दिए हैं।

भारत ने कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (सीसीडीबी) का अध्यक्ष पद संभाला

(जीएनएस)।

भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (सीसीडीबी) का अध्यक्ष बनाया गया है। अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा मानक निर्धारण में देश की बढ़ती भूमिका को दशार्ती है। इस उच्च पद का निर्णय 14 से 16 अप्रैल 2026 के बीच टोक्यो, जापान में हुई कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट (सीसीआरए) की पहली तिमाही की बैठक के दौरान किया गया।

कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट (सीसीआरए) एक मूलभूत अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो सीमा पार आईटी सुरक्षा प्रमाणपत्रों को आपसी मान्यता देता है। उच्च स्तरीय नीति कमेटियों के अलावा, सीसीआरए खास वर्किंग समूहों और प्रशासनिक प्रोटोकॉल के जरिए कार्य करता है, जिन्हें कॉमन क्राइटेरिया पोर्टल की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो दुनियाभर में प्रमाणित सुरक्षा आईटी उत्पादों के लिए "सत्य का एकल स्रोत" के तौर पर कार्य करता है।

सीसीडीबी, सीसीआरए की तकनीकी कोर के रूप में कार्य करता है, जो कॉमन क्राइटेरिया (सीसी) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इवैल्यूएशन (सीईएम) के लिए सामान्य कार्यप्रणाली के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य प्रोग्राम को संचालित करता है। जबकि दूसरे सीसीआरए समूह नीतिगत मामलों को संभालते हैं, सीसीडीबी उन तकनीकी मानकों और मूल्यांकन मानदंडों पर फोकस करता है जो ग्लोबल आईटी उत्पादों को सुरक्षित करते हैं।

भारत 16 सितंबर, 2013 से प्रमाणपत्र अधिकृत करने वाले राष्ट्र के तौर पर सीसीआरए का एक सक्रिय सदस्य रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय (टएकळ) और एसटीक्यूसी महानिदेशालय के जरिए कार्य करता है, जो भारत में आईटी सुरक्षा मूल्यांकन के लिए अधिकृत प्रमाणपत्र संस्था हैं।

सीसीआरए के नियमों के मुताबिक, सामान्य मानदंडों के तहत मूल्यांकित किए गए उत्पादों के लिए सदस्य देशों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को बिना पुनः प्रमाणीकरण के परस्पर मान्यता दी जाती है, जिससे सुरक्षित आईटी उत्पादों में बिना किसी रुकावट के इंटरनेशनल ट्रेड हो पाता है। सीसीआरए में 20 सर्टिफिकेट-ऑथराइज़िंग राष्ट्र और 18 सर्टिफिकेट-कंज्यूमिंग राष्ट्र शामिल हैं। ये देश मिलकर कॉमन क्राइटेरिया पोर्टल की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करते हैं, जो प्रमाणित सुरक्षित आईटी उत्पादों के लिए प्रामाणिक ग्लोबल रिपॉजिटरी के तौर पर कार्य करता है।

भारत का सीसीडीबी अध्यक्ष पद संभालना देश की तकनीकी क्षमता और ग्लोबल आईटी सुरक्षा मानकों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यह लीडरशिप भूमिका भारत को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मूल्यांकन के तरीकों को तय करने में सबसे आगे रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि उभरती प्रौद्योगिकियां, खासकर भारत के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क में ठीक से शामिल हों। दो साल की यह अवधि भारत को दुनियाभर में आईटी सुरक्षा प्रमाणन के भविष्य को बनाने वाले जरूरी फैसलों पर प्रभाव डालने का अवसर प्रदान करती है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में अब 5-दिवसीय कार्य सप्ताह, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में पहल

(जीएनएस)।

लखनऊः यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय ने वैश्विक ऊर्जा संकट और संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी के निर्देश पर विश्वविद्यालय में अब सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को अपनाने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पहला संस्थान बन गया है.

कुलसचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय और शैक्षणिक कक्षाएं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगी. दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक भोजनावकाश रहेगा. हालांकि, पूर्व निर्धारित परीक्षाएं पहले से जारी समय-सारिणी के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी.

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए लिया गया है. सप्ताह में एक दिन परिसर बंद रहने से बिजली, ईंधन और अन्य संसाधनों की बड़ी बचत होगी. साथ ही परिवहन और संचालन संबंधी खर्चों में भी कमी आएगी.

कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक युद्ध और ऊर्जा संकट को देखते हुए हमें संसाधनों के प्रति गंभीर होना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण के आह्वान को ध्यान में रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह पहल की है. यह निर्णय न सिर्फ ऊर्जा बचत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि कार्यक्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगा.

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों और छात्रों को बेहतर कार्य-संतुलन मिलेगा. वहीं संस्थान ऊर्जा मितव्ययिता के राष्ट्रीय अभियान में भी अपनी प्रभावी भागीदारी निभाएगा.

प्रमुख बिंदु

यूपी की पहली राज्य यूनिवर्सिटी जिसने 5-डे वर्किंग कल्चर अपनाया

ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों की बचत को बढ़ावा

प्रधानमंत्री के 'ऊर्जा बचत' संदेश को धरातल पर उतारने की पहल

बिजली और परिवहन संसाधनों की होगी बड़ी बचत

कार्यक्षमता और प्रशासनिक संचालन में आएगा सुधार

सीएम योगी और मंत्रियों के काफिले से हटेंगी 50% गाड़ियां, योगी ने की वर्क फॉर्म होम को प्राथमिकता देने की अपील

योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक और संसाधनों की बचत के आह्वान से जुड़ने की भावुक अपील की है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल को देखते हुए हर नागरिक को सावधानी बरतनी होगी.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक और संसाधनों की बचत के आह्वान से जुड़ने की भावुक अपील की है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल को देखते हुए हर नागरिक को सावधानी बरतनी होगी. उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद न करने का सुझाव दिया ताकि देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिल सके.

जानें जरूरी जानकारी ?

इस मुहिम की शुरूआत मुख्यमंत्री ने स्वयं के स्तर से करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है. उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में तत्काल 50 प्रतिशत वाहनों की कमी की जाए और अनावश्यक गाड़ियों को हटाया जाए. साथ ही, उन्होंने सरकारी अधिकारियों

को निर्देश दिए कि सचिवालय और अन्य विभागों की बैठकें, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस यथासंभव वर्चुअली आयोजित की जाएं.

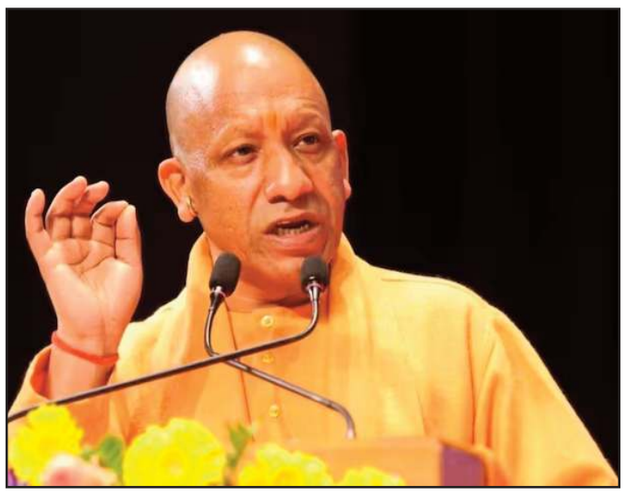

मेट्रो की सुविधा की प्राथमिकता ?

परिवहन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 'नो व्हीकल डे' और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग पर विशेष बल दिया है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और छात्रों से अपील की कि वे सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो या बस का उपयोग करें. जहां मेट्रो की सुविधा है, वहां इसके अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की भी बात कही और सुझाव दिया कि निजी संस्थानों में भी सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था की जाए.

ऊर्जा संरक्षण और स्वदेशी को बढ़ावा देना भी इस अपील का मुख्य हिस्सा है. मुख्यमंत्री ने अनावश्यक बिजली खर्च न करने और रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों का प्रयोग न्यूनतम करने को कहा है. उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में 'विजिट माई स्टेट' अभियान पर जोर देते हुए लोगों से अगले छह माह तक अनावश्यक विदेशी यात्राएं टालने और देश के भीतर ही पर्यटन एवं डेस्टिनेशन वेडिंग करने का आग्रह किया है.

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के संगम के रूप में खाद्य तेल के उपयोग में कमी लाने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी. स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और ओडीओपी (ODOP) सामग्री को उपहार के रूप में उपयोग करने की सलाह देते हुए उन्होंने 'स्वदेशी' को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया है. कुल मिलाकर, यह योजना प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करने की तैयारी

(जीएनएस)।

उन्नाव/अचलगंज। कानपुर-लखनऊ के बीच 64 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड/ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे (एनई-6) बनकर तैयार हो गया है। प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब इस एक्सप्रेसवे का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण कराने की तैयारी शुरू की है। सूत्रों के अनुसार स्थान तय होने के बाद मुख्यमंत्री भी किसी दिन स्थलीय निरीक्षण करने आ सकते हैं। 24 या 25 मई को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो सकता है।

गुरुवार को डीएम घनश्याम मीना, एसपी जयप्रकाश सिंह, एनएचएआई के परियोजना निदेशक परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के आयोजन के लिए कानपुर-लखनऊ हाईवे (एनएच 27) की तरफ उन्नाव और कानपुर के बीच आजाद मार्ग चौराहा और उन्नाव-लालगंज हाईवे पर कोरारी के पास बनाए गए एक्सप्रेसवे कट के पास जनसभा स्थल के लिए जगह देखी। हालांकि अधिकारी अभी प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम घोषित होने या प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसी कोई सूचना मिलने से इन्कार कर रहे हैं। एनएचएआई के पीडी नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि लोकार्पण के 15 से 20 दिन पहले आधिकारिक सूचना जारी होती है। हालांकि बृहस्पतिवार तक कोई सूचना या कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। किसी भी दिन लोकार्पण कराया जा सकता है।

45 मिनट में कानपुर से लखनऊ, 275 रुपये टोल टैक्स

इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में सुरक्षित चलकर 45 मिनट में सफर पूरा कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए वाहन स्वामियों हाईवे की अपेक्षा ज्यादा टोल टैक्स भी देना होगा। एनएचएआई के सूत्रों के अनुसार लखनऊ-कानपुर हाईवे की अपेक्षा इस एक्सप्रेसवे पर करीब 25 प्रतिशत अधिक टोल टैक्स लगेगा। सूत्रों के अनुसार एक तरफ के लिए टोल टैक्स 275 रुपये और आना-जाना 415 रुपये में होगा। हालांकि यातायात शुरू करने से पहले एनएचएआई टोल की दरें घोषित करेगा।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक नजर

-कुल लंबाई-64 किलोमीटर

-उन्नाव में लंबाई-45,3

-लागत-3100 करोड़ रुपये

चढ़ने-उतरने की सुविधा

-उन्नाव-लालगंज हाईवे पर अचलगंज कोरारी गांव के पास

-लखनऊ-कानपुर हाईवे पर आजाद मार्ग चौराहा के पास

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 200 मेगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन राष्ट्र को समर्पित की

(जीएनएस)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की 200 मेगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है और भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा महासागर-आधारित ऊर्जा प्रणालियों सहित विभिन्न गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का तेजी से विस्तार कर रहा है।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की अपनी उपयोगिता और महत्ता है तथा भारत स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और सतत विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की सचिव तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी, सीईएल के सीएमडी श्री चेतन जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक, सीईएल के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में नवीकरणीय ऊर्जा और स्वदेशी प्रणालियों के विकास से जुड़े क्षेत्रों में सीएसआईआर प्रयोगशालाओं और सीईएल के बीच महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पहलों की भी शुरूआत हुई।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 200 मेगावाट

सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन के संचालन को भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि यह सुविधा स्वदेशी विनिर्माण तथा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के प्रति देश के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सीईएल के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत का पहला सौर सेल वर्ष 1977 में सीईएल द्वारा निर्मित किया गया था तथा देश का पहला सौर संयंत्र भी वर्ष 1979 में इसी संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि इतनी अग्रणी उपलब्धियों के बावजूद उस समय सीईएल के योगदान को वह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार थी, लेकिन अब यह संस्था पुनः राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रासंगिकता प्राप्त कर रही है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विनिवेश के कगार पर पहुंच चुकी संस्था से लाभ अर्जित करने वाली और राजस्व उत्पन्न करने वाली मिनी रत्न कंपनी के रूप में सीईएल का परिवर्तन संस्थागत पुनरुत्थान का उल्लेखनीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव दृढ़ नेतृत्व, नीतिगत समर्थन, संचालन अनुशासन तथा संगठन से जुड़े वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

मंत्री ने नई निर्माण लाइन की स्थापना की गति की सराहना की। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण 24 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था, एक माह के भीतर सफल बोलीदाता का चयन कर लिया गया और एक वर्ष से भी कम समय में विनिर्माण सुविधा का संचालन प्रारंभ हो गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीईएल अब वर्टिकल एक्सिस पवन टर्बाइन, हाइब्रिड नवीकरणीय प्रणालियां, डेटा सेंटर, उन्नत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तथा छोटे हथियार प्रणालियों जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है, जो भारत के बढ़ते तकनीकी आत्मविश्वास और रणनीतिक तैयारी को दर्शाता है।

रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार के नीतिगत सुधारों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को अधिक निजी भागीदारी के लिए खोला है तथा उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर आगे बढ़ रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली (एडब्ल्यूओएस) तथा नई पीढ़ी की दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर प्रणाली के लिए सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं और सीईएल के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहलों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकियों को उद्योग साझेदारी के माध्यम से व्यावसायीकरण और जन उपयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

मंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि नई पीढ़ी की दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर प्रणाली अब पूर्ण रूप से स्वदेशी बन चुकी है और कहा कि स्वदेशी प्रौद्योगिकियां राष्ट्रीय आत्मविश्वास, विनिर्माण क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करती हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 200 मेगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का राष्ट्र को समर्पण विकसित भारत 2047 की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है तथा यह वैज्ञानिक उत्कृष्टता को राष्ट्रीय विकास में परिवर्तित करने की भारत की बढ़ती क्षमता को दशार्ता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में NDRF को 'प्रेसिडेंट्स कलर' प्रदान किए जाने के समारोह को मुख्य अतिथि के तौर संबोधित किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (ठऊफ्रक्ष) को 'प्रेसिडेंट्स कलर' प्रदान किए जाने के समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (क्ढ) के निदेशक और ठऊफ्रक्ष के महानिदेशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि ठऊफ्रक्ष को 'प्रेसिडेंट्स कलर' प्रदान किया जाना सिर्फ ठऊफ्रक्ष की सराहनीय सेवाओं को स्वीकार किया जाना ही नहीं, बल्कि यह रऊफ्रक्ष पंचायत से लेकर राज्य तक पूरी मशीनरी, ठउउ, ठरर और हजारों की संख्या में सेवा में लगे आपदा मित्रों की सेवाओं का राष्ट्रपति महोदया द्वारा अनुमोदन किया जाना है। उन्होंने कहा कि ठऊफ्रक्ष के जवान देश में कहीं भी 'आपदा सेवा सदैव सर्वत्र' के घोष के साथ जाते हैं। ठऊफ्रक्ष के जवान देश-दुनिया में जहाँ कहीं भी गए, वहाँ प्यार और भरोसा अर्जित किया है। देश में कहीं भी आपदा आई हो या आने वाली हो, जब ठऊफ्रक्ष के जवान वहाँ पहुँचते हैं, तो जनता राहत की साँस लेती है कि अब उनका बचाव हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि ठऊफ्रक्ष ने अपनी स्थापना के 20 साल में देश में कहीं भी बाढ़, भूकंप, चक्रवात या किसी अन्य प्रकार की आपदा आई हो, अपने सफल कार्यों के आधार पर पूरे देश की 140 करोड़ जनता का विश्वास अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या कोई भीषण हादसा, ठऊफ्रक्ष की एक झलक ही देशवासियों के मन में सुरक्षा और भरोसे का भाव भर देती है। इस बल ने अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है और 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ठऊफ्रक्ष को प्रेसिडेंट्स कलर मिलना, ठऊफ्रक्ष के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ठऊटअ) और ठऊफ्रक्ष ने अपने कार्यकाल में आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर स्थापित करने का काम किया है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है, लेकिन देश के गृह मंत्री के नाते मेरे लिए यह विशेष गौरव का विषय है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली छह परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से ठऊफ्रक्ष देश की जनता को किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षित रखने के लिए और भी मजबूती से काम कर पाएगी।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से अब तक हमने न केवल आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए काम किया है, बल्कि अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब हम जीरो कैजुअल्टी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जिस आपदा का पूवार्नुमान और मौसम विज्ञान विभाग से पूर्व जानकारी मिल जाती है, वहाँ जन, धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य होता है। उन्होंने कहा कि ठऊटअ ने आपदा प्रबंधन से जुड़े नीति विषयक मामलों में ढेर सारे निर्णय लिए, बहुत सारे दिशानिर्देश जारी किए, और जन जागरूकता पैदा करने की दिशा में सफल प्रयास किए, जिसकी वजह से धीरे-धीरे आपदा बचाव देश का संस्कार बनता जा रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि ठऊफ्रक्ष ने न केवल नागरिकों, बल्कि उनके साथ रहने वाले मूक पशुओं को भी बचाकर उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आपदा में जनहानि शून्य हो और संपत्तियों का नुकसान न्यूनतम हो।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय हीट वेव जैसी गंभीर चुनौतियों का भी बहुत ही प्रभावी तरीके से सामना करने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार हीट वेव से होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक लाने की दिशा में कार्य कर रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय और ठऊफ्रक्ष ने क्षमता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी पर बहुत बल दिया है। ठऊफ्रक्ष ने अपने 8,500 से अधिक जवानों, 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस कर्मियों और 2 लाख 20 हजार से अधिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का भागीरथ कार्य किया है। उन्होंने कहा कि दो वर्षों में 10,500 से अधिक नाविकों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

गृह मंत्री ने कहा कि कम्युनिटी बेस्ड आपदा रिस्पॉन्स को मजबूत करने के लिए आपदा मित्रों की टोली हर खतरे का मुकाबला करने में उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि पहले आपदा प्रबंधन में प्रतिक्रिया राहत-आधारित थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव और प्रोडक्टिव बनाया है। आपदा के कहर से जानमाल का नुकसान न्यूनतम करने के विषय को प्रधानमंत्री मोदी जी ने न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में एक थ्योरी के रूप में स्थापित किया है।

अपराधियों की नींद उड़ा रहा 'कन्विक्शन', लखनऊ जोन में 4 महीने में 457 दोषियों को मिली सजा

(जीएनएस)।

इन दिनों उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में एक अनकहा भय तैर रहा है। थानों की दीवारों, अदालतों के गलियारों और जेलों की बैरकों के बीच एक नया शब्द तेजी से गूंज रहा है...'कन्विक्शन'।

कभी अपराधियों के बीच यह भरोसा सबसे बड़ा कवच हुआ करता था कि 'मुकदमा चलता रहेगाङ्ग'। हत्या करने वाला जानता था कि गवाह टूट जाएंगे। दुष्कर्मी जानता था कि पीड़ित परिवार अदालतों के चक्कर काटते-काटते थक जाएगा। गैंगस्टर जानता था कि कानून की प्रक्रिया लंबी है और समय सबसे बड़ा बचाव पक्ष होता है।

रात के किसी सन्नाटे में जब कोई मां अपनी बेटी को लेकर भयभीत होती है, जब किसी गांव की पगडंडी पर किसी हत्या के बाद पसरा हुआ सन्नाटा पूरे समाज को डरा देता है, जब कोई विधवा अदालतों के चक्कर काटते-काटते बूढ़ी हो जाती हैङ्ग तब केवल अपराध नहीं होता, समाज का विश्वास भी घायल होता है।

उत्तर प्रदेश में वर्षों तक अपराध का सबसे बड़ा दुस्साहस यही था कि अपराधी को कानून से अधिक अपनी पहुंच और पैरवी पर भरोसा रहता था।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी त्रासदी केवल अपराध नहीं थी, बल्कि अपराध के बाद न्याय का लंबा इंतजार था। पीड़ित मरता एक बार था, पर अदालत की हर तारीख पर थोड़ा-थोड़ा फिर मरता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है।

अब उत्तर प्रदेश में अपराध केवल दर्ज नहीं हो रहा, उसका पीछा अदालत के अंतिम फैसले तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के नेतृत्व में चल रहा 'ऑपरेशन कन्विक्शन' दरअसल इसी 'नए उत्तर प्रदेश' की सबसे निर्णायक कहानी है।

यह केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं है। यह अपराध और दण्ड के बीच टूट चुकी दूरी को समाप्त करने का प्रयास है। यह एफआईआर दर्ज करके फाइल बंद कर देने वाली मानसिकता का अंत है। यह उस सोच का प्रतिकार है, जिसमें अपराधी गिरफ्तारी से नहीं, केवल सजा से डरता है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने यह तय किया कि अपराधी को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अदालत से दण्ड दिलाना ही असली सफलता होगी।

इसी सोच के साथ लखनऊ जोन, जिसमें सीतापुर, खीरी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, अयोध्या, सुलतानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर और अमेठी शामिल हैं, ने 01 जनवरी 2026 से 10 मई 2026 तक कुल 328 अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाई। इन मामलों में 457 अभियुक्त दोषसिद्ध हुए।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने 13 कोर्सों का परीक्षा कार्यक्रम किया जारी, 26 से LLB की परीक्षाएं

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एलएलबी तीन वर्षीय, एलएलबी इंटीग्रेटेड सहित परास्नातक के 13 पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी है। परीक्षाओं की शुरूआत 22 मई से होगी। विस्तृत समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

परीक्षा विभाग के अनुसार एम.काम (दो वर्षीय) चौथे सेमेस्टर (सीबीसीएस) और इसके ओल्ड कोर्स, एम.ए/एम.एससी एंथ्रोपोलाजी चौथे सेमेस्टर, एम.ए, एम.एससी फारेंसिक साइंस चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई से तीन जून तक होंगी।

एलएलबी तीन वर्षीय चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई से 16 जून, इसके छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से 12 जून और एलएलबी इंटीग्रेटेड चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से 15 जून, इसके छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई से 16 जून, आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 26

मई से 13 जून और 10वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से तीन जून तक होंगी।

इसी तरह एम.ए एंड एम.एससी (सांख्यिकी) चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 मई से पांच जून, एम.ए/एम.एससी (बायो स्टैटिस्टिक्स) चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 मई से पांच जून, एम.एससी जियोलाजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 मई से एक जून तक होंगी।

एम.ए पर्शियन चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं दो से चार जून, एम.ए वीमेंस स्टडीज चौथे सेमेस्टर और एम.ए ज्योर्तिविज्ञान सीबीसीएस चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई से तीन जून तक संचालित की जाएंगी।

इसी तरह एम.एससी अप्लाइड जियोलाजी (सीबीसीएस) चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं छह से 15 जून, एम.ए/एम.एससी (गणित) सीबीसीएस, एम.ए (इंग्लिश) और एम.ए फ्रेंच चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से तीन जून तक होंगी। वहीं, एम.ए डिफेंस स्टडीज चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 मई से एक जून तक आयोजित की जाएंगी।

विकसित भारत के लिए - कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण और समावेशी विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन

(जीएनएस)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विकसित भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण तथा समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह सम्मेलन ङ्गभागीदारी से भाग्योदयङ्घ (यानी सहभागिता के माध्यम से समृद्धि) की थीम पर आधारित था। इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका उद्देश्य भागीदारी आधारित शासन, सहकारी संघवाद और तकनीक के माध्यम से बेहतर जनसेवा प्रदान करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण को मजबूत बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना था।

यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच था, जहां भारत सरकार के विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक विकसित, समावेशी और समानता आधारित राष्ट्र के दृष्टिकोण - नीतिगत संवाद, हितधारकों से परामर्श और सहयोगात्मक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ए आई शिखर सम्मेलन के बाद कहा था कि हर मंत्रालय अपने कामकाज में आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाए। इसके अपील के अनुरूप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस दिशा में पहल करते हुए बातचीत आधारित ए आई बॉट्स विकसित करने की शुरूआत की है, ताकि

अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक प्रभावी और बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ श्री वत्स कृष्ण ने इस सम्मेलन को एक खुला मंच बताया, जहां केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सार्थक संवाद, समस्याओं के समाधान और नए व नवाचारपूर्ण विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला। मंत्रालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर संस्थागत सहयोग और समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं।

मंत्रालय के सचिव महोदय के संबोधन के केंद्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी भूमिका रही, जो शासन और सार्वजनिक प्रशासन को आधुनिक बनाने में अहम योगदान दे सकती है। मंत्रालय ने बताया कि ए आई आधारित उपकरण भविष्य में निगरानी तंत्र को मजबूत करने, शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने, डेटा आधारित निर्णय को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचे।

इस सम्मेलन में व्यापक स्तर पर चर्चा और परामर्श हुआ, जिसमें भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों, प्रचालन संबंधी समस्याओं और जमीनी स्तर के मुद्दों को सामने रखा। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की और इन समस्याओं पर स्पष्ट मार्गदर्शन व व्यावहारिक समाधान प्रदान किए।

कौशल विकास और समन्वय

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा संचालित विशेष सत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत समन्वय पर बाल दिया गया। इस दौरान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहलों और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल के अवसरों पर चर्चा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अल्पसंख्यक युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और उनके लिए बेहतर आजीविका के अवसर तैयार करना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें।

जनरेशन इंडिया ने एक विस्तृत सत्र प्रस्तुत किया, जिसमें ए आई आधारित और तकनीक-संचालित समाधानों के मध्य से कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पर प्रकाश डाला गया। इस सत्र में विश्व स्तर पर बेहतरीन पद्धतियों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें कार्यबल को तैयार करने के आधुनिक तरीके, रोजगार मैपिंग की प्रभावी रणनीतियां और परिणाम-आधारित कार्यान्वयन ढांचे शामिल थे।